सवाई माधोपुर जिले के 13 प्रतिष्ठानों में नियोजित 4171 अंशदाताओं को वार्षिक लेखा विवरण जारी नहीं किए गए हैं। इन में से मैसर्स जयपुर उद्योग लि०, सवाई माधोपुर और फालोदी क्वार्री में नियोजित 3970 अंशदाताओं को वार्षिक लेखा-विवरण इस लिए जारी नहीं किए गए कि उक्त कारखाने तथा उक्त क्वार्री में 1975–76 में लगभग 8 महीने काम नहीं हुआ था और प्रबन्धकों ने इस अवधि के दौरान अपेक्षित रिटर्न भी प्रस्तुत नहीं की थी। इन मैसर्स के सम्बन्ध में लेखा समाधान कार्य चल रहा है। यह लेखा विवरण तथा 201 शेष लेखा विवरण की शीघ्र नहीं जारी किए जाने की आशा है। इन 13 प्रतिष्ठानों की सूची संलग्न है जिसमें उन अंशदाताओं की संख्या दर्शाई गई है जिन्हें लेखा-विवरण अभी जारी किए जाने हैं।

(ग) जयपुर म क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में सवाई माधोपुर जिले के भविष्य निधि सदस्यों के सम्बन्ध में राशि वापस लेने सम्बन्धी कोई मामला अनिर्णीत नहीं पड़ा है।

(घ) राजस्थान के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने सूचित किया है, कि जो पत्रादि उनके कार्यालय में प्राप्त होते हैं, उनकी ओर तत्काल ध्यान दिया जाता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रमांक	प्रतिष्ठान का नाम	अंशदाताओं की संख्या
1.	मैसर्स जयपुर उद्योग लि० सवाई माधोपुर	2500
2.	मैसर्स जयपुर उद्योग लि० फालोदी, क्वार्री	1470
3.	मैसर्स सवाई माधोपुर सहकारी भूमि विकास बैंक लि०, सवाई माधोपुर	25
4.	मैसर्स जेठमल हीरालाल, गंगापुर शहर	6
5.	मैसर्स श्रीनिवास राइस एण्ड आयल मिल्स, गंगापुर शहर	4
6.	मैसर्स शुभ लक्ष्मी इंडस्ट्रीज, गंगापुर शहर	29
7.	मैसर्स गंगापुर कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लि०, गंगापुर शहर	17
8.	मैसर्स गणेश राइस मिल्स, गंगापुर शहर	7
9.	मैसर्स ग्रामसेवा मंडल, करौली	40
10.	मैसर्स घेनरे लाल जैन, बिर्धी चन्द जैन, करौली	25
11.	मैसर्स तिवाड़ी झूमर लाल, करौली	36
12.	मैसर्स शाह कस्तूर मल गोडी सोप-स्टोन. माइन, डाकघर मोरांइ, जिला सवाई माधोपुर	13
13.	मैसर्स अभिनन्दन आयल एण्ड फ्लोर मिल्स, गंगापुर शहर।	2
	जोड़	4171

Control on G. C. I. Sheets

10002. SHRI HALIMUDDIN AHMED: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether there is control over the price of G.C.I. Sheets;

(b) if so, the control price per ton;

(c) whether Government has fixed any specific quota for public consumption, if so, the procedure for its distribution;

(d) whether it is a fact that the public has to purchase G.C.I. sheets in open market on payment of Rs. 300/- per ton; and

(e) whether Government propose to supply G.C.I. sheets to fire sufferers on control rate?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA): (a) to (c). There is no control either on distribution or pricing of any category of iron and steel (including GCI sheets) and as such the question of fixing of any specific quota for public consumption does not arise.

(d) Market prices of GCI sheets vary from place to place and from time to time depending on its demand and availability at that time.

(e) Since there is no control either on pricing or distribution of iron and steel, the question of supply at "Control rate" does not arise.

Mini Steel Plants in India

10003. SHRI AHMED M. PATEL: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) the number of mini-steel plants Functioning in India with their location;

(b) the number of mini steel plants proposed to be installed during the next two years; and

(c) the areas selected?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA): (a) As in March, 1978, there were 124 commissioned units in different States as indicated below:—

S. No.	Name of State	No. of commissioned units
1.	Andhra Pradesh . .	5
2.	Bihar	6
3.	Delhi	1
4.	Gujarat	3
5.	Haryana	12
6.	Himachal Pradesh . .	1
7.	Karnataka	9
8.	Kerala	1
9.	Madhya Pradesh . .	8
10.	Maharashtra . . .	23
11.	Punjab	8
12.	Rajasthan	7
13.	Tamil Nadu	3
14.	Uttar Pradesh . . .	19
15.	West Bengal	18
		24

(b) and (c). Out of 145 units holding licences for a capacity of 3.3 million tonnes per year, only 124 units having a capacity of 2.82 million tonnes per year, as mentioned above, have so far been commissioned. The remaining 21 units are in various stages of implementation in the States of Assam, Andhra Pradesh, Gujarat, Kerala, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and West Bengal.

राजकोट के साथ ट्रंक एक्सचेंज के डायरेक्ट सर्किटों से जोड़े गये शहर

10004. श्री धर्म सिंह भाई पटेल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में सौराष्ट्र प्रदेश के राजकोट शहर के साथ ट्रंक एक्सचेंज के डायरेक्ट सर्किटों से अब तक किन-किन शहरों को जोड़ दिया गया है ;

(ख) 31 मार्च 1979 तक और कितने अतिरिक्त शहरों या नगरों को राजकोट की डाइरेक्ट सर्किटों से—लाइनों से जोड़ा जाएगा ; और

(ग) इसके लिए क्या कार्यक्रम है और इनका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) अहमदाबाद, गांधीनगर और जामनगर से राजकोट के लिए सीधे डायल घुमा कर टेलीफोन करने की सुविधा उपलब्ध है।

(ख) बड़ौदा, सूरत ।

(ग) राजकोट और बड़ौदा आटोमेटिक, एक्सचेंजों को अहमदाबाद के ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज के साथ जोड़ने का काम चल रहा है और आशा है कि यह काम मार्च, 1979 तक पूरा हो जाएगा। इस व्यवस्था से राजकोट और बड़ौदा के बीच आपस में डायल करने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।

Portariats of National Leaders in Indian Embassies

10005. SHRI SAMAR GUHA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether pictures of Indian National Leaders are usually displayed in the offices of our foreign missions;